(b) the countries to which export of shoes is the maximum;

(c) how many leather and non-leather shoes are exported; and

(d) what steps are being taken to boost the shoes export?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Value of exports of footwear (which includes shoes, chappals etc.) with break-up of leather and non-leather footwear during the last three years for which figures are available, were as follows:—

(Value in Rs. crores)

	1990-91	1991-92	1992-93
Leather footwear	290.94	492.64	526.77
Non-leather footwear	628.50	669.45	697.91
TOTAL	919.44	1162.09	1224.68

(SOURCE : DGCI&S, Calcutta. Quantitative figures for shoes are not maintained)

USA, Germany and UK are the major buyers of the Indian Footwear.

(d) Export of footwear including shoes is a thrust sector of our exports and a number of measures have been taken to boost exports. These inter-alia include setting up of a Footwear Design & Development Institute, setting up of Design Studios with CAD/CAM facilities, organising an International Shoe Fair for the first time in India and launching a National Leather Development Programme with UNDP assistance for an integrated development of the industry.

Agricultural commodities not being allowed for export

7394. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the agricultural commodities which are not being allowed to be exported;

(b) the reasons behind not allowing such exports;

(c) what justification is there to prohibit exports when the economy is being liberalised; and

(d) whether this is not an injustice to the agricultural sector?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (d) The prohibited items of export in the agriculture and allied sectors are detailed in Part I of the Negative List of Exports of the Exim Policy 1992-97. These include all forms of wild animals, exotic birds, endangered species of plants, beet tallow, fat and/or oils of animal origin, wood and wood products, sandal wood and red sanders wood. These items are not allowed for export due to environmental reasons and public sentiment etc.

While maximising foreign exchange earnings from the agricultural sector to the benefit of th e farmers, the strategy of the Govt. is to allow the export of items of mass consumption in such a manner that it does not compromise our food security, With this objective in mind, Govt. have also placed restrictions like licensing, quantitative

ceilings and minimum export prices etc. on pulses, cereals, oilseeds, milk and milk products, sugar, etc.

"गैट" संधि के उपरांत आयात और निर्यात की जानें वाली वस्तुएं

7395. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" संधि पर हस्ताक्षर के बाद किन-किन ऐसी वस्तुओं का आयात और निर्यात अब शुरू हो जाएगा, जिनका अब तक आयात अथवा निर्यात नहीं हो रहा था ;

(ख) क्या "गैट" संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध होंगे ; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से देश हैं, जिन्होंने गैट संधि पर हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं परन्तु भारत के उनसे व्यापारिक संबंध बने हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सटकर और व्यापार संबंधी आम करार (गाट) और इससे संबंधित मुद्दों में इसके सदस्यों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने वाले नियमों का प्रावधान है । विशिष्ट वस्तुओं का उल्लेख नहीं है । गाट सदस्यों और गैर सदस्यों के बीच व्यापार संबंधों पर भी ध्यान नहीं देता ।

सदस्य और गैर सदस्यों के बीच होने वाला व्यापार द्विपक्षीय करारों या संबंधित देशों की अपनी-अपनी व्यापार नितियां द्वारा जैसा भी मामला हो, शासित होता है ।

गाट के 123 सदस्य हैं और गाट की सदस्यता के लिए 17 देशों का अनुरोध विभिन्न स्तरों पर है । 69 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम व्यापार करते हैं वे गाट के सदस्य नहीं हैं । ये हैं कैनरी आइसलैंड, केप वार्डे आर्टलैण्ड, कामासेस, जिबूती, इथोपोया इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, साइबेरिया, रीयूनियन, संट हेलेना आफ एजेन्सन, लीबिया, सूडान, ग्रीनलैण्ड, सैंट पियरे एण्ड मिक्विलान, बहमार, मोंटसराट अमेरिकन समोआ, ब्रिटिश वर्लिन आइसलैण्ड, केमान, आई लैण्ड, फाकलैण्ड, आइलैण्ड, गुडीलोप, मार्टिनिक, पनामा, केनाल जोन, पुर्टोरिको, तुर्कस आर क्युकांस आकलण्ड, यू. एस. का वर्जिनि आइलैण्ड, अफगानिस्तान, भूटान, क्रिसमस आइ लैण्ड, कुक आइलैंड, ईरान, किरिबतो गणराज्य, लाओमीपुत्स डिमाक्रेटिव रिपब्लिक मंगोलिया, नौरन गणराज्य, नेपाल, पापुआ और न्यूगिनी, सोलोमान आइलैण्ड, टोंगा, तुवालू वियतनाम, वेस्टर्न समोआ, इराक, लोबनान, ओमान, सीरिया, यमन अरब गणराज्य, यमन पीपुल्स डमोक्रेटिक रिपब्लिक, काकोस आइलण्डै, फ्रेंच गुयाना, फ्रेचपोलीनिया, गुयाम, न्यू कैनिया, न्यू हेब्राइड्रस, मियू आइलैण्ड, नारफाक आइलैण्ड, पैसिफिक आइ लैण्ड, पिरईरियन आइलैण्ड, पुर्तगाल टाइमर, टोकलांऊ आइलैण्ड, वालिस और फुटुना आइलैण्ड, रिपब्लिक आफ वानुआल, फैरो प्रायद्वीप, अण्डोरा, चेनल आइलैण्ड और जिब्राल्टर ।

Granting of patent for transgenic soyabean

7396. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that granting of patent for transgenic soyabean by European Union to Agracetus Inc. would adversely affect our use of transgenic soyabean;

(b) whether transgenic cotton patented by Agracetus/Grace in India is revoked;

(c) if so, the reason therefor and the details of how the patent of transgenic cotton would have adversely affected our rice cultivators and agro-research;